पत्र नहीं मित्र

देशबन्धु

.नई दिल्ली, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020 | वर्ष-12 | अंक-279 | पृष्ठ - 14 | मूल्य - 4.00 रुपए

मामला

आवासीय परियोजना शुरू करने से बढ़ता है रोजगार

रियल एस्टेट को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा : एसोचैम

नई दिल्ली, 20 जनवरी (एजेंसियां)। रियलटी क्षेत्र को पटरी पर लाने और मांग बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग को अगले वित्त वर्ष के बजट में विशेष राहत दिए जाने की अपील करते हुए इस क्षेत्र ने किफायती आवास वर्ग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने की उम्मीद जताई है।

क्रेडाई की किफायती आवास समिति के अध्यक्ष मनोज गौड़ कहा कि आगामी बजट को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है क्योंकि यह एक ऐसा दिन हो सकता है जब बहुत सारे नीतिगत फैसलों को रियल एस्टेट सेक्टर के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए घोषित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि रियलटी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है और उम्मीद है कि बजट में इस दिशा में कोई घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक आवासीय परियोजना शुरू किए जाने पर न सिर्फ हजारों मजदूर को रोजगार मिलता है बल्कि 150 से अधिक उद्योगों को भी ऑर्डर मिलते हैं और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेंडिट की फिर से शुरुआत की जानी चाहिए। इसे पिछले वर्ष वापस ले लिया गया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ के साथ, संपत्ति की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। जीएसटी के दायरे में स्टांप

ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क भी लाना अगर बजट में शामिल होता है तो इसकी बहुत सराहना की जाती। मध्यम आय वर्ग को आवास खरीदने पर अधिक छूट दिए जाने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में आयकर छूट सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को अपने आवास खरीदने के लिए

- **मध्यम वर्ग को घर खरीदने पर अधिक छूट दिए जाने की मांग**
- **जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुरुआत करना जरूरी**

प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे सरकार के वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को भी हासिल करने में मदद मिलेगी।

उद्योग संगठन एसोचैम की राष्ट्रीय परिषद (किफायती आवास) के अध्यक्ष एवं सिग्नेचर ग्लोबल के संस्थापक प्रमुख प्रदीप अग्रवाल ने किफायती आवास क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने की अपील करते हुए कहा कि यह बहुत पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की दिशा में निवेश के बारे में पिछले साल जो घोषणाएं की गई थीं।

अग्रवाल ने कहा कि बजट में किफायती आवास के विकास के लिए बड़े शहरों में सस्ती जमीन उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए जिससे लोग घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे और अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन की राशि को दोगुना किए जाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इससे अधिक लोगों का घर बनाने का सपना साकार हो सकेगा।